

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,  
प्रमुख सचिव, वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/  
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून :: दिनांक : २७-मार्च, 2008

विषय: -वित्तीय वर्ष 2008-2009 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किया जाना।

महोदय,

वर्ष 2008-2009 के आय-व्यय की मांगे स्वीकृत होने व तत्सम्बन्धी विनियोग अधिनियम, 2008 पारित होने के फलस्वरूप आवश्यक वचनबद्ध मदों हेतु वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन, महंगाई भत्ते, अन्य भत्ते तथा अनुदान के रूप में सरकारी सेवकों तथा गैर सरकारी सेवकों के वेतन एवं वचनबद्ध मदों में मजदूरी, विद्युत देय, जलकर किराया, पेंशन, औषधि, भोजन व्यय, पेट्रोल, टेलीफोन, मानदेय, कार्यालय व्यय, सामग्री सम्पूर्ति तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति जैसे आवश्यक व्ययों का भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2008-2009 के बजट की समस्त धनराशि प्रशासनिक विभाग/बजट नियंत्रक अधिकारी द्वारा आहरण-वितरण अधिकारी के निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-आयोजनागत पक्ष की पूँजीगत चालू योजनाएं, जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक भौतिक वित्तीय प्रगति हो चुकी है तथा अवमुक्त धनराशि का 75 प्रतिशत से अधिक व्यय हो चुका हो, के लिए प्रशासनिक विभाग अपने स्तर पर परीक्षणोपरान्त वित्तीय स्वीकृति जारी करेंगे तथा यह ध्यान रखेंगे कि फण्ड की पार्किंग न हो ताकि राज्य सरकार पर अनावश्यक रूप से ओवरड्राफ्ट या अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज की अधिक देनदारी न हो। 50 प्रतिशत से कम वित्तीय/भौतिक प्रगति से सम्बन्धित योजनाओं/प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु परिव्यय/बजट की सीमान्तर्गत ही वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त स्वीकृति जारी की जायेगी।

3-आयोजनागत पक्ष की नई योजनाओं के प्रस्ताव पर स्वीकृति जारी करने से पूर्व परिव्यय एवं बजट की उपलब्धता देखते हुए नियोजन/वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आयोजनेतर पक्ष की योजनाओं के लिए वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

4-आयोजनागत पक्ष के राजस्व पक्ष में उपरोक्त प्रस्तर-1 में वर्णित स्थिति को छोड़कर शेष योजनाओं की स्वीकृति नियोजन विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्गत की जायेगी। जारी की गई स्वीकृति आदेश की प्रति महालेखाकार, उत्तराखण्ड तथा वित्त विभाग को पृष्ठांकित की जाएगी।



5-वित्तीय वर्ष 2008-09 में शासनादेश संख्या 624/जि0यो0 / मु0स0 / 2008, दिनांक 24 मार्च, 2008 के द्वारा जिला योजना की स्वीकृतियों के लिए जिलाधिकारी तथा मण्डलायुक्त स्तर पर अधिकार प्रतिनिधित्व किए गए हैं। 2008-09 हेतु प्राविधानित जिला योजना की धनराशि जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रख दी जाय ताकि अनुमोदित जिला योजनाओं की जनपद/मण्डल स्तर पर ही समयवद्ध वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी हो सकें तथा विकास कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण भी हो सके।

6-प्रायः यह देखा गया है कि प्रशासनिक विभागों द्वारा धनराशि विभागाध्यक्षों के निवर्तन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण-वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है। अतः प्रशासनिक विभाग यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विभागाध्यक्षों तथा अन्य नियंत्रक अधिकारियों के निस्तारण पर जो धनराशि रखी गई है वह उनके द्वारा आहरण-वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए और फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो। प्रशासनिक विभाग प्रत्येक माह वित्त विभाग को विभागाध्यक्षों द्वारा आहरण-वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0-17 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

7-अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग अनिवार्य रूप से वित्त विभाग को उपलब्ध करायेंगे, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।

8-व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टैक्निकल स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यों हेतु पूरे वर्ष के सम्भावित व्यय की फेजिंग करके प्रशासकीय विभाग कार्यदायी संस्थाओं को अवगत करायेंगे तथा लक्ष्य के अनुसार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा/अनुश्रवण किया जाना अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा। लोक निर्माण, सिंचाई, वन आदि विभाग जहाँ साख सीमा की व्यवस्था है, वहाँ पर साख सीमा की त्रैमासिक सीमा उसी प्रकार निर्धारित किया जाय, जैसा कि शासनादेश संख्या - ए-2-311/दस-98, दिनांक 29 जून, 1998 के प्रस्तर 2 (2) एवं 2 (3) में निर्धारित है, परन्तु यदि उस त्रैमास में साख सीमा की धनराशि व्यय होने में कोई कठिनाई होती है तो अवशेष धनराशि अगले त्रैमास तक व्यय करने की अनुमति देने हेतु वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी तथा साख सीमा जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारी इसे अपने स्तर से जारी कर सकते हैं।

9-जिन अनुदानों में राजस्व अथवा पूंजीगत पक्ष में वित्तीय वर्ष 2008-2009 में एकमुश्त व्यवस्था का प्राविधान है, ऐसी स्वीकृतियों के जारी किये जाने के पूर्व बजट मैनुअल के पैरा - 94 में उल्लिखित दिशा - निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय।

10-नियोजन विभाग समय-समय पर जिला योजना की ऐसी योजनाओं की समीक्षा करेगा जिनमें पदों का सृजन या केन्द्रीयित क्रय निहित है तथा जहाँ प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से आवश्यकता है, उन योजनाओं को राज्य सैक्टर में स्थानांतरित करना सुनिश्चित करेगा।

11-केन्द्रपोषित योजनाओं के राज्यांश की धनराशि केन्द्रांश प्राप्त होने के उपरान्त जारी की जायेगी। जिन केन्द्रीय योजनाओं हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त है अथवा केन्द्र सरकार की बचनबद्धता परिलक्षित होती है, ऐसी योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करने के लिए वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त अग्रिम के तौर पर आंशिक वित्तीय स्वीकृति जारी की जा सकती है।



12-प्रत्येक प्रशासनिक विभाग वर्ष के प्रारम्भ में तथा हर माह की 10 तारीख तक वित्त एवं नियोजन विभाग को केन्द्र सहायतित/ बाह्य सहायतित योजनाओं में अनुमोदित परिचय के सापेक्ष केन्द्रांश की धनराशि तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई धनराशि का विवरण उपलब्ध कराएंगे। जिन विभागों से यह सूचना प्राप्त नहीं होगी उनके वित्तीय अधिकारों पर रोक लगा दी जाएगी। केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली अवशेष धनराशि का विवरण भी प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाएगा।

13-जिन योजनाओं में विगत वर्षों की प्रतिपूर्ति प्राप्त की जानी अवशेष हो उन प्रशासकीय विभागों के सचिवों का यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। भारत सरकार को समय से आडिट की हुई प्रतिपूर्ति के देयक प्रस्तुत किये जाय, ताकि इसके अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई/विलम्ब न हो।

14-किसी अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का बगैर वित्त विभाग की सहमति के किसी स्तर से किसी भी प्रकार के पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। यदि पुनर्विनियोग हेतु वित्त विभाग की सहमति अनुदान के अधीन दी जाती है, तब पुनर्विनियोग स्वीकृति आदेश पर वित्त विभाग द्वारा आदेश विशिष्ट पत्र संख्या का प्रयोग कर उसकी प्रति महालेखाकार (उत्तराखण्ड) को उपलब्ध कराया जाय। प्रशासनिक विभागों द्वारा वित्त विभाग को पुनर्विनियोजन का प्रस्ताव बजट मैनुअल के पैरा-151 के अन्तर्गत प्रस्ताव का परीक्षण करने के उपरान्त ही भेजा जाये। यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्व पक्ष से पूंजी पक्ष तथा पूंजी पक्ष से राजस्व पक्ष में भी पुनर्विनियोजन प्रतिबंधित है।

15-जैसा कि बजट मैनुअल पैरा- 88 में इंगित किया गया है, नियंत्रक अधिकारी या विभागाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो और सचिवालय के सम्बन्धित विभाग इस बात को सुनिश्चित करने के उत्तरदायी होंगे कि विभागीय सचिवों/प्रमुख सचिवों के स्तर पर भी वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाय। बी0 एम0 - 13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग को प्रतिमाह विलम्बतम 20 तारीख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध करायी जाय। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना समय से भेजा जाना सुनिश्चित करना प्रशासनिक विभाग का उत्तरदायित्व है, जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

16-बाह्य सहायतित परियोजनाओं, अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत आबंटित परिचय के सापेक्ष बजट प्राविधान की स्वीकृतियां तत्परता से जारी कर दी जायें तथा किसी भी दशा में उक्त हेतु बजट में की गई व्यवस्था को अन्य योजना हेतु व्यावर्तित न किया जाय। बाह्य सहायतित परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग यह सुनिश्चित कर लें कि डोनर एजेंसी एवं भारत सरकार के साथ सभी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं। इस आधार पर अग्रिम के तौर पर बजट की स्वीकृति हेतु वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त स्वीकृति जारी की जायेगी। व्यय की गयी समस्त धनराशि की प्रतिपूर्ति चालू वित्तीय वर्ष में ही प्राप्त करने हेतु प्रशासनिक विभाग पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।

17-प्रशासनिक विभाग, विशेष रूप से वे विभाग जहाँ केन्द्रीयित क्रय प्रक्रिया लागू है, या दर अनुबन्ध किये जाते हैं, वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होते ही एक प्रोक्योरमेंट प्लान बना लेंगे। इसी प्रकार पूंजीगत कार्यों का भी एक एक्सन प्लान तैयार कर वित्त/ नियोजन विभाग को उपलब्ध कराएंगे।

18-यह उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय - समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।


19-यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो निर्माण कार्य आरम्भ किए जा चुके हैं वे यथाशीघ्र पूर्ण किये जा सकें, प्रशासनिक विभाग प्रत्येक माह विभाग द्वारा स्वीकृत कार्य, आंगणन की धनराशि, निर्गत वित्तीय स्वीकृत इत्यादि का विवरण संलग्न प्रपत्र 1 से 4 पर वित्त विभाग/ नियोजन विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

20-अनुदानों को विभागवार एवं विभागाध्यक्षवार तैयार करने के कारण एक ही लेखाशीर्षक अनेक अनुदानों के अन्तर्गत प्रदर्शित होता है, जिसके फलस्वरूप महालेखाकार के कार्यालय में व्यय को सही लेखाशीर्षक/अनुदान के अन्तर्गत पुस्तान्कित करने में कठिनाई होती है और सुसंगत लेखाशीर्षक/अनुदान के अधीन त्रुटि रह जाने की संभावना बनी रहती है। इस हेतु यह आवश्यक है कि सभी वित्तीय स्वीकृतियां शासनादेश संख्या - बी-2-2337/ -97, दिनांक 21 नवम्बर, 1997 के प्रारूप में सही लेखाशीर्षक इंगित करते हुए ही निर्गत की जाये, जो बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्य किया जाये। बजट नियंत्रक अधिकारी बी0 एम0 - 17 पर आवंटन सम्बन्धी विवरण तथा आवंटन आदेश हेतु निर्धारित प्रारूप पर आहरण-वितरण अधिकारियों को बजट आवंटन तथा जिस अधिकारी का नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागारों में परिचालित हो, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर की धनराशियां पूर्व निर्गत शासनादेशों के क्रम में जारी करेंगे अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा, जिसके लिये सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

प्रत्येक विभाग में स्वीकृतियों का रजिस्टर रखा जाय एवं प्रत्येक माह में स्वीकृति/व्यय सम्बन्धी सूचना शासनादेशों की प्रतियों सहित वित्त एवं नियोजन विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,


  
(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या 267 (1)/XXVII(1)/2008 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून।
2. समस्त विभागाध्यक्ष।
3. समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. शासन के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

  
(एल0एम0 पन्त) 27/3/2008  
अपर सचिव, वित्त



सबन निर्माण कार्यो की प्रगति का विवरण (31-03-2008 तक)

[illegible]

भवन निर्माण कार्यों की प्रगति का विवरण (31-03-2008 तक)

C:\Users\hewang\Downloads

## निर्माण कार्यों की प्रगति समीक्षा

पूर्ण परन्तु हस्तान्तरित न हुए भवनों का विवरण (31-03-2008 तक)

(मननाशि रमण ने)

[illegible]

निर्माण कार्यों की प्रगति समीक्षा

केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्र से प्राप्त धनराशि का विवरण।  
वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2007-08 (प्रत्येक वर्ष के लिए अलग शीट पर)

[illegible]